भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1310

11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

"झारखंड में एचईसीएल का जीर्णोद्धार"

1310. श्री राजेश रंजनः

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना बनाई है/बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों को लगभग तीन वर्षों से लंबित वेतन के भुगतान के लिए कोई ठोस कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारस्वामी)

(क): जी नहीं।

(ख): उपर्युक्त भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। अतः, यह एक अलग विधिक इकाई है। इसलिए, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए इसे अपने स्वयं के संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

लगातार घाटे के कारण एचईसी इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अनियमित हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों को साढ़े चार महीने का निवल वेतन दिया जा चुका है। वर्तमान में कर्मचारियों और अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों का संचयी बकाया वेतन क्रमशः 25 महीने और 29 महीने का है।

*****